यूरोपीय संघ के साथ व्यापार की बात

लेखक - मोहन कुमार (अध्यक्ष, रिसर्च एंड इनफार्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कन्ट्रीज) और कॉन्स्टेंटिनो जेवियर (फेलो, फॉरेन पॉलिसी स्टडीज, ब्रुकिंग्स इंडिया)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

27 अगस्त, 2019

"भारत के लिए मुक्त व्यापार समझौते पर यूरोपीय संघ के साथ बातचीत जल्द से जल्द करना क्यों आवश्यक है।"

जैसा कि हम देख रहे हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अमेरिकी-चीन व्यापार युद्ध से पीड़ित होना शुरू हो गयी है, इसलिए भारत के लिए यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करना अनिवार्य हो गया है। हालांकि, पिछले महीने, दोनों पक्षों के वार्ताकार ब्रुशेल्स में इस संदर्भ में बात आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मिले थे, लेकिन नई दिल्ली के लिए समय की मांग इस मुद्दे पर जल्द से जल्द सफलता पाना है।

अमेरिका और चीन से आगे बढ़ते हुए, भारत के लिए अनुकूल भू-आर्थिक व्यवस्था को तैयार करने हेतु यूरोपीय संघ को एक अनिवार्य लोकतांत्रिक भागीदार के रूप में शामिल करने का यह सही समय है। आर्थिक और भू-रणनीतिक कारकों की एक श्रृंखला यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक समझौते की आवश्यकता को और अधिक जरूरी बनाती है।

सबसे पहला, बिगड़ती वैश्विक व्यापार व्यवस्था, बढ़ते संरक्षणवाद और द्विपक्षीय एफटीए की खराब स्थिति के बीच भारत पीछे होता जा रहा है। भारत एकमात्र शीर्ष शक्ति है जिसके पास यूरोपीय संघ, अमेरिका, चीन और खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं सहित अपने किसी भी शीर्ष व्यापारिक भागीदार के साथ एफटीए का अभाव है और यह स्थिति ऐसी है जिसे नजरंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ज्यादातर व्यापार अब एफटीए या वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं द्वारा संचालित होता है।

एफटीए पर यूरोपीय संघ द्वारा दुबारा ध्यान देना भारत के लिए जोखिम को बढ़ा सकता है। जून में, ब्रुशेल्स ने वियतनाम के साथ एक व्यापार सौदा और दक्षिण अमेरिका में मर्कोसुर (Mercorsur) देशों के साथ एक ऐतिहासिक एफटीए का समापन किया। इस बीच, भारत अपने मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन, Most Favoured Nation, MFN) की स्थिति पर लटका हुआ है। यूरोपीय संघ की सामान्यीकृत योजना (जीएसपी) के तहत इसकी स्थिति पाकिस्तान या श्रीलंका से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करेगी, जो जीएसपी और इससे होने वाले लाभ का आनंद उठा रहे हैं।

'ग्रे जोन' की दुविधा

ग्रे जोन (grey zone) में फंसने के बाद, एफटीए टैरिफ या जीएसपी की स्थिति के बिना, भारत यूरोप के लिए निर्यात को प्रतिस्पर्धी रखने के लिए संघर्ष करेगा, इसका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जहाँ यह 20% निर्यात करता है।

यहाँ अच्छी खबर यह है कि यूरोपीय संघ के साथ भारत की वार्ता धीरे-धीरे, लेकिन तेजी से आगे बढ़ रही है। कृषि से बौद्धिक संपदा तक, यूरोपीय संघ और भारत चुपचाप विचारों का आदान-प्रदान और सरेखण कर रहे हैं। ई-कॉमर्स जैसे नए क्षेत्रों ने महत्वपूर्ण अभिसरण दर्ज किया है क्योंकि डेटा गोपनीयता पर भारत की स्थिति ईयू से अलग नहीं है। यूरोपीय संघ-जापान समझौते के साथ, भारत

दो तरह की गति के साथ आगे बढ़ना चाहेगा; जहाँ यह कुछ वर्षों के लिए डेटा के मुक्त प्रवाह से संबंधित चर्चा में देरी कर सकता है और अन्य क्षेत्रों में भी उदारीकरण के लिए प्रतिबद्ध होने के बावजूद कर अधिस्थगन मुद्दे या डेटा स्थानीयकरण पर मतभेदों को स्थिर रख सकता है।

दूसरा, केवल आर्थिक लागत-लाभ विश्लेषण से ही नहीं, बल्कि भारत को भू-सामरिक दृष्टिकोण से भी यूरोपीय संघ एफटीए से संपर्क करना चाहिए। भारत पर श्री ट्रम्प का रुख और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के बारे में व्याप्त चिंताओं को देखते हुए, नई दिल्ली को यूरोप के साथ एक व्यापार समझौते के दीर्घकालिक रणनीतिक लाभों का एहसास होना चाहिए।

लोकतांत्रिक नियम

यूरोपीय संघ के वार्ताकार अब श्रम या पर्यावरणीय नियमों पर रियायतें देने के लिए अधिक इच्छुक हैं, जो कि पहले अड़चनकारी बाधाएं थीं। ट्रांसअटलांटिक व्यापार और निवेश साझेदारी के पतन और चीन पर अत्यधिक आर्थिक निर्भरता के बारे में चिंताओं ने यूरोपीय संघ को थोड़ा और व्यावहारिक बनने के लिए प्रेरित किया है, जिसका नई दिल्ली द्वारा काफी देर होने से पहले लाभ उठा लेना चाहिए। यूरोपीय संघ भारत को एक अद्वितीय नियामक मॉडल भी प्रदान करता है जो विकास, गोपनीयता और मानकों को संतुलित करता है। भारत का शासन ढांचा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने से लेकर 5G नेटवर्क तक, कई नए तकनीकी डोमेन पर लोकतांत्रिक पारदर्शिता और बहु-हितधारक भागीदारी के यूरोपीय मानदंडों को साझा करता है।

नई दिल्ली को इसे एक ऐसे रणनीतिक प्रीमियम के रूप में देखना चाहिए जिसका किसी भी लागत-लाभकारी आर्थिक विश्लेषण में कोई योगदान नहीं है।

जब नई दिल्ली एक बहुध्रुवीय क्रम को बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक साझेदार के रूप में यूरोप की बात करता है, तो उसे सुरक्षा से परे जाकर और व्यापार एवं प्रौद्योगिकी के व्यवसाय से शुरू करना चाहिए।

GS World टीम...

मुक्त व्यापार समझौता (Free trade agreement-एफटीए)

क्या है?

- मुक्त व्यापार समझौता या एफटीए के तहत दो देशों के बीच आयात-निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को सरल बनाया जाता है। मुक्त व्यापार समझौता का प्रयोग व्यापार को सरल बनाने के लिये किया जाता है।
- इससे यह लाभ होता है कि जिन दो देशों के बीच में यह समझौता किया जाता है, उनकी उत्पादन लागत बाकी देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है।
- इसके लाभ को देखते हुए दुनिया भर के बहुत से देश आपस में मुक्त व्यापार समझौता कर रहे हैं।
- इससे व्यापार को बढ़ाने में मदद् मिलती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इससे वैश्विक व्यापार को बढ़ाने में भी मदद् मिलती रही है। हालाँकि कुछ कारणों के चलते इस मुक्त व्यापार का विरोध भी किया जाता रहा है।
- ऐसे समझौते करने के लिये देशों या देशों के समूहों को WTO के दायरे में आने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिये WTO के नियमों से अगर उन्हें कहीं रुकावट हो रही हो, तो वे एफटीए के सहारे भी आगे बढ़ सकते हैं।
- मुक्त व्यापार टैरिफ को समाप्त करता है तथा कॉर्पोरेशन को विदेशी बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाता है।

- एफटीए में आमतौर पर वस्तुओं (जैसे-कृषि या औद्योगिक उत्पाद) या सेवाओं के व्यापार (जैसे-बैंकिंग, निर्माण, ट्रेडिंग इत्यादि) को कवर किया जाता है।
- एफटीए बौद्धिक संपदा अधिकार, निवेश, सरकारी खरीद और प्रतिस्पर्द्धी नीति आदि जैसे अन्य क्षेत्रों को भी कवर कर सकता है।

आवश्यकता क्यों?

- एफटीए भागीदारों के लिए टैरिफ और कुछ गैर-टैरिफ बाधाओं के खत्म होने से एक-दूसरे के बाजारों में पहुँच आसान होती है।
- निर्यातक बहुपक्षीय व्यापार उदारीकरण के लिये एफटीए को पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें गैर-एफटीए सदस्य देश के प्रतिस्पर्द्धियों पर अधिमान्य सहूलियत मिलती है। उदाहरण के लिये, आसियान के मामले में, आसियान का भारत के साथ एफटीए है लेकिन कनाडा के साथ नहीं।
- एफटीए से बाहर विदेशी निवेश में वृद्धि की संभावना होती है, जबकि मुक्त व्यापार समझौते मुक्त व्यापार और निवेश प्रवाह को बढ़ावा देते हैं।
- एफटीए व्यापार उत्पादकता और नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं। इससे क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलता है।
- एफटीए विकासशील देशों की मदद् कर सकते हैं तथा इससे व्यापार का माहौल गतिशील होता है।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)

- यह दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के दस सदस्यीय देशों तथा छः अन्य देशों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड), जिनके साथ आसियान का मुक्त व्यापार समझौता है, के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है।
- आर.सी.ई.पी. भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह वैश्विक जीडीपी का 25 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार का 30 प्रतिशत, एफडीआई प्रवाह का 26 प्रतिशत और कुल आबादी का 45 प्रतिशत है।
- साथ ही यह विश्व व्यापार के लगभग 40 प्रतिशत भाग को कवर करेगा।
- आर.सी.ई.पी. वार्ता की औपचारिक शुरुआत 2012 में कंबोडिया में आयोजित 21वें आसियान शिखर सम्मेलन में शुरू हो गई थी।
- आर.सी.ई.पी. को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

सदस्य देश

- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।
- इनके अलावा, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड सहभागी देश हैं।

Committe

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **मुक्त व्यापार समझौता (FTA) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

   1. इसकी संकल्पना सर्वप्रथम 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशन्स' में सामने आई थी।
   2. इसमें वस्तुओं या सेवाओं का व्यापार किया जाता है।
   3. इसके अन्तर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार, निवेश, सरकारी खरीद और प्रतिस्पर्धी नीति क्षेत्र भी आता है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements regarding Free Trade Agreement (FTA)-**

   1. It was envisaged for the first time in 1776 in the book of Adam Smith " The wealth of Nation"
   2. Here goods and services are traded.
   3. Intellectual Property Rights, investment, government procurement and competetive policy sectors also comes under it.

   Which of the above statements is/are correct?

   (a) Only 1 (b) Only 2

   (c) 1 and 2 (d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: भारत का अपने शीर्ष व्यापारिक भागीदार देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का अभाव है। वर्तमान में अमेरिका-चीन व्यापारिक युद्ध के कारण बिगड़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारत का यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता कितना आवश्यक है? चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

Q. India lacks Free Trade Agreement (FTA) with its top trade partners. Presently to what extent the Free Trade Agreement of India with Europen Union is important in the light of the falling global economy due to deepening trade war between America and China? Discuss.

(250Words)

नोट : 26 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।